

विहगावलोकन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

1.1 वर्ष 2005 के दौरान अर्थव्यवस्था में ऊंची वृद्धि जारी रही और वैश्विक स्तर पर इसमें में 4.9%¹ की वृद्धि हुई। यह लगातार तीसरा वर्ष है जिसमें वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 4.0 प्रतिशत से अधिक हुई है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की शक्ति, अपनी पिछले लंबे समय के औसत 3.8 प्रतिशत से अधिक रहने के साथ-साथ प्रणाली गत भारी आघातों को झेलने की क्षमता प्राप्त करती है। इन आघातों में तेल के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वैश्विक स्तर पर उत्पादन में वृद्धि का अगुआ उदीयमान एशिया रहा। 2005 के दौरान वैश्विक उत्पादन में वृद्धि का आधे से अधिक हिस्सा एशिया का ही रहा जबकि अमरीका और यूरोप में वर्ष के दौरान कम दर से वृद्धि हुई है। एशिया में 2005 में हुई भारी वृद्धि में चीन (10.2), भारत (8.4), हांगकांग (7.3) द्वारा, अग्रणी रहे हैं। बहुप्रतीक्षित जापान के पुनरुत्थान से एशिया क्षेत्र में न केवल नई सक्रियता को बल मिलेगा, बल्कि उससे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) देशों में भी वृद्धि को बल मिलेगा। रूस और लैटिन अमरीका में भी वृद्धि उत्साहवर्धक रही है। अमरीका में तेल की उँची कीमतों, अल्पावधि ब्याज दरों में वृद्धि, आवास निर्माण बाजार में मंदी और सितंबर में हरिकेन तूफान के कारण सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2004 के 3.9% से घटकर 2005 में 3.2% हो गई। यूरो क्षेत्र में, वर्ष 2005 के दौरान सुधार जारी है तथा सकल घरेलू उत्पाद में 1.3% की वृद्धि हुई।

1.2 वर्ष 2005 में विश्व भर में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ी है जो तेजी से बढ़ते तेल की कीमतों के कारण होनेवाले दबावों की सूचक है। अधिक तेजी से बढ़ती मांग के कारण (विशेष रूप से उदीयमान एशिया में), यहां तक कि ऊर्जा से इतर वस्तुओं की कीमतों में 2005 में वृद्धि का रुख देखने में आया, यद्यपि 2005 के मुकाबले यह वृद्धि दर कम रही है। वर्ष 2005 के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका में खाड़ी तट पर दो विनाशकारी तूफानों, मध्य एशिया में तनाव, अन्य तेल निर्यातक देशों में राजनैतिक अशांति और कम क्षमता निर्माण के कारण तेल के बाजार में अत्यधिक अनिश्चितता बनी रही। तेल कीमतों में अंतरराष्ट्रीय वृद्धि का घरेलू खुदरा कीमतों पर पड़ने वाला प्रभाव भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न मुद्रास्फीति

का सूचक रहा। 2005 के दौरान स्फीति का प्रभाव तेल और तेल से इतर कीमतों में वृद्धि के बावजूद कम ही रहा।

1.3 संयुक्त राज्य अमरीका का चालू खाता घाटा, विश्व भर में वृद्धिशील ब्याज दर के माहौल के कारण 800 बिलियन डॉलर के स्तर को पार कर गया, पूरे विश्व में ब्याज दरों में वृद्धि हुई और वैश्विक वित्तीय बाजारों में पर्याप्त चलनिधि की स्थिति के साथ वर्ष 2005 के दौरान वैश्विक वित्तीय असंतुलन और बढ़ गया। संयुक्त राज्य अमरीका के चालू खाता शेष में और गिरावट के बावजूद वित्तीय बाजार शांत रहे।

1.4 वैश्विक अर्थव्यवस्था में वृद्धि की उक्त प्रवृत्ति, वित्तीय बाजार में कम उतार-चढ़ाव, और सुदृढ़ लाभप्रदता के माहौल में 2005 में निवेशक अपेक्षाकृत अधिक कीमतों पर जोखिम पूर्ण आस्तियों की खरीद के लिए तैयार रहे। प्रमुख विदेशी मुद्रा ब्याज दर और इक्विटी बाजार में ऑप्शन कीमतों द्वारा किए गए अंतर्निहित उतार चढ़ाव से निपटने के उपाय कई वर्षों में न्यूनतम स्तर पर रहे जो इस बात के सूचक हैं कि बाजार इस उम्मीद पर काम कर रहे हैं कि ये अनुकूल गतिविधियां जारी रहेंगी। प्रमुख मुद्रा क्षेत्रों में वास्तविक अल्पावधि और दीर्घावधि ब्याज दरें दीर्घावधिक दरों के औसत से बहुत नीचे रहीं। जापान, यूरो क्षेत्र और अमरीका में 10 वर्षीय बांडों पर होने वाला लाभ क्रमशः 1.9%, 3.9% और 5.0% रहा। इन गतिविधियों के साथ ही पूरी दुनिया में, आस्ति मूल्यों के मामले में जोखिम प्रीमियम बहुत कम बना रहा। अनेक देशों में आवास की कीमतों में तेजी रही। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में इक्विटी कीमतों में पिछले अनेक वर्षों के मुकाबले अधिक वृद्धि हुई। ऋण के प्रसार की गति अत्यंत धीमी होने के साथ-साथ ऋण वृद्धि में तेजी की गति 1990 के दशक के अंतिम भाग की तरह रही। इस सामान्य रुख का प्रमुख अपवाद वस्तुओं की कीमतें रहीं, जिसमें हाल के वर्षों में पर्याप्त उतार चढ़ाव देखने में आया।

1.5 परंतु बड़ी मात्रा में राजकोषीय घाटा, कुछ विकसित अर्थ व्यवस्थाओं (विशेष रूप से अमरीका) में अत्यंत निम्न घरेलू बचत, कम कार्पोरेट निवेश और वैश्विक चालू खाता भारी असंतुलन वर्तमान वैश्विक वृद्धि के लिए चुनौती बने हुए हैं।

¹ इस अध्याय में जब तक कि इससे भिन्न न निर्दिष्ट किया गया हो वैश्विक गतिविधियों का संबंध कैलेंडर वर्ष जनवरी से दिसंबर से है जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े राजकोषीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) से संबंधित हैं।

वर्ष 2006 के दौरान गतिविधियाँ

1.6 वर्ष 2006 की पहली छमाही में वैश्विक वृद्धि ने तेज गति पकड़ी और लगता है कि यह प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में फैल गई। वैश्विक वृद्धि वर्ष 2005 के 4.9% से बढ़कर 2006 में 5.1% हो जाने की आशा है (अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, 2006) । संयुक्त राज्य अमरीका में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में वृद्धि की दर पहली और दूसरी तिमाहियों की क्रमशः 5.6 प्रतिशत और 2.6 प्रतिशत की तुलना में कम, 1.6 प्रतिशत दर्ज हुई । संयुक्त राज्य अमरीका की अर्थव्यवस्था में मंदी की भरपाई विश्व के अन्य भागों में होने वाली मजबूत वृद्धि से होने की आशा है। सितंबर 2006 में जारी किए गए अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक के अनुसार, 2006 में यूरो क्षेत्र में वृद्धि बढ़कर 2.4 प्रतिशत होने की संभावना है - छह वर्ष में सबसे अधिक दर -2007 में संशोधित करके 2.0 प्रतिशत करने से पहले, 2007 में 2.1 प्रतिशत तक होने से पहले, मजबूत घरेलू मांग के कारण जापानी अर्थ व्यवस्था का 2006 में 2.4 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है । उदीयमान बाजारों और विकासशील देशों में 2006 में 7.3 प्रतिशत की दर से सुदृढ़ रहने और 2007 में 7.2 थोड़ी कम वृद्धि होने की संभावना है।

1.7 विकसित अर्थ व्यवस्थाओं में उपभोक्ता कीमतों में स्फीति दूसरी तिमाही में तेजी से बढ़ी। परंतु सितंबर 2006 के दौरान कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज गिरावट के कारण पड़े प्रभाव के मद्देनजर कुछ राहत नजर आई। अमरीका में उपभोक्ता कीमतें जून 2006 में बढ़कर 4.3% हो गईं जो अप्रैल 2006 में 3.5% थी परंतु सितंबर 2006 में घटकर 2.1 प्रतिशत हो गई जिसका प्रमुख कारण तेल की कीमतों में परिवर्तन है। यूरो क्षेत्र में भी स्फीति में मई और जून में 2.5% वृद्धि हुई जो अप्रैल में 2.4% थी; यह सितंबर 2006 में 1.8 प्रतिशत थी। प्रमुख औद्योगिक देशों में स्फीति में वृद्धि तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई लगती है। कच्चे तेल की कीमतें अप्रैल 2006 से बढ़ना शुरू हुईं और पिछले 2 वर्षों में हुई वृद्धि से बहुत बढ़ कर लगभग दुगुना हो गईं जो कि 14 जुलाई 2006 को 78.7 डॉलर प्रति बैरल की उच्चतम सीमा तक पहुंच गई। उसके बाद, सितंबर 2006 के उत्तरार्ध में कीमतों में तेजी से कमी आई और वह 60 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल हो गई तथा अक्टूबर 2006 में, विश्वभर में मांग की कमी के अनुमान, ईरान में न्यूक्लियर कार्यक्रम में नरमी के कारण तनाव में कमी तथा अमरीकी मालसूचियों में भारी वृद्धि के मद्देनजर 60 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गई। यद्यपि पिछले एक माह से अधिक समय से कीमतों में भारी कमी आई है, फिर भी वे अभी भी बहुत ऊंची

बनी हुई हैं। हालांकि अभी हाल में वह प्रवृत्ति उल्टी हो गई है। अधिकतर वस्तुओं की कीमतों में ज्यादा वृद्धि हुई है। यद्यपि वृद्धि का प्रमुख कारण तेल और धातुओं की कीमतों में वृद्धि रही है तथापि खाद्य पदार्थों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। सांकेतिक और स्फीति सूचकांकित बांडों के बीच स्फीति का प्रभाव भी बढ़ा है जो अमरीका में मई से जुलाई 2006 के दौरान 2.2 से 2.7 प्रतिशत के बीच था।

1.8 वास्तव में वैश्विक बाजार में हाल की उथल-पुथल, प्रमुख पण्यों की कीमतों में वृद्धि के कारण नजर आती है। इसके अतिरिक्त, तेल की कीमतों में अगली वृद्धि, भू-राजनैतिक तनाव, चालू खाता असंतुलन का विनाशकारी समायोजन तथा वैश्विक आवास निर्माण के बाजार में मंदी के कारण दूसरे चरण के प्रभावों का खतरा मंडरा रहा है।

1.9 वैश्विक असंतुलन, जो कि प्रमुख रूप से अमरीका के दोहरे घाटे और जिसका प्रभाव प्रमुख मुद्राओं में ठीक से संतुलन न बिठा पाने के कारण विश्व स्तर पर बढ़ती ब्याज दरों तथा वैश्विक वित्तीय बाजार में चलनिधि के संकुचन की संभावना के वतावरण में 2006 में अंतर बढ़ते रहे। इसका समायोजन अन्य स्थानों पर हुए अधिशेषों, विशेष रूप से चीन, यूरोप और उदीयमान एशिया के अन्य भागों एवं तेल निर्यातक देशों में से पूरा हुआ। अमरीका की निवल विदेशी देयता में हुई वृद्धि से प्रमुख मुद्राओं में अचानक तथा अव्यवस्थित समायोजन का खतरा उत्पन्न हो गया है।

1.10 वित्तीय बाजार वैश्विक स्तर पर बढ़ते असंतुलन के अव्यवस्थित समायोजन के खतरे की आशंका से ग्रस्त हो रहे हैं। वैश्विक स्तर में स्टॉक एक्स्चेंजों में भारी गिरावट और स्पष्ट रूप से ऋण के लिए बढ़ती पसंद का दुष्प्रभाव बाजार में देखने में आया। दीर्घावधि श्रेष्ठ प्रमुख बांडों पर होने वाली आय, जो थोड़ी बढ़ गई थी पुनः पिछले लंबी अवधि के औसतों से नीचे गिर गई है और प्रमुख औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में आय वक्र या तो सपाट हो गया है या अस्तव्यस्त हो गया है। इन वैश्विक परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में अधिकतर केंद्रीय बैंकों ने अभी हाल में अपने सरकारी ब्याज दरों को इस दशक में पहले की अत्यंत कम दरों से बढ़ाकर अधिक कर दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

व्यापक परिवेश

1.11 भारतीय अर्थव्यवस्था में 2005-06 के दौरान 8.4% की दर से अच्छी-खासी वृद्धि जारी रही जो कि पिछले वर्ष 7.5 प्रतिशत थी। 2003-04 और 2005-06 के दौरान औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 8.1% था। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वर्ष

2005-06 में वृद्धि कृषि में सुधार तथा उद्योग एवं सेवाओं में निरंतर विस्तार की प्रमुखता के कारण थी। कृषि और सहबद्ध कार्यकलापों से होने वाले वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 3.9% दर्ज की गई जो कि पिछले वर्ष में 0.7% की निम्न दर से सुधर रही है। उद्योग से होने वाली वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुमान के अनुसार वर्ष 2005-06 में, 7.6% थी जो पिछले वर्ष 7.4% थी। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के आधार पर औद्योगिक उत्पादन 2005-06 के दौरान 8.2 प्रतिशत की दर से तेजी से बढ़ा जो एक साल पहले अधिकतम 8.4% थी। घरेलू और निर्यात मांग में निरंतर वृद्धि तथा क्षमता के अधिक उपयोग के कारण, विनिर्माण क्षेत्र की सुदृढ़ता को और सहारा मिला। 2005-06 के दौरान सेवा क्षेत्र की वृद्धि द्विअंकीय 10.3% बनी रही जोकि पिछले वर्ष के 10.2% से थोड़ा-सा अधिक है। वर्ष 2005-06 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3/5 की हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र भारतीय आर्थिक विकास में अग्रणी रहा।

1.12 थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) में वर्ष दर वर्ष मापी गई हेड लाइन स्फीति का चढ़ाव-उतार मार्च 2006 के अंत में 4.1% था जो एक साल पहले के 5.1% के मुकाबले कम था। परंतु स्फीति दर की परिवर्तनीयता वर्ष के दौरान काफी उतार-चढ़ाव वाली रही। अप्रैल 2005 में स्फीति लगभग 6.0% के आसपास थी, जो फलों और सब्जियों, लोहा और इस्पात तथा पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की सूचक है। बाद में मानसून के अच्छा होने पर स्फीति कम होने लगी और वर्ष के दौरान 27 अगस्त 2005 को 3.3% के निम्नतम स्तर पर आ गई। यह स्फीति 2005-06 की तीसरी तिमाही के दौरान पुनः बढ़ी परंतु सितंबर 2005 की शुरुआत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव के कारण और सब्जियों की उच्चतर कीमतों के कारण 5.0% के नीचे बनी रही। जनवरी से मार्च 2006 के दौरान सब्जियों की कीमतों में कमी तथा घरेलू लोहा और इस्पात की कीमत में गिरावट के कारण स्फीति कम रही जिससे अलौह धातुओं तथा विद्युत के द्वारा उर्ध्वमुखी दबाव समायोजित होते रहे। तेल की कीमतों की वृद्धि के कारण उत्पन्न आपूर्ति संबंधी दबावों के बावजूद 2005-06 के दौरान हेड लाइन स्फीति अनुमान से कम रही। स्फीति की प्रत्याशाओं पर अंकुश लगाने में अनेक कारकों का योगदान रहा जैसे मौद्रिक नीति संबंधी एहतियाती कार्रवाई, रिवर्स रेपो दर में वृद्धि के रूप में, तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में परिवर्तन का घरेलू मूल्यों पर अपूर्ण प्रभाव, अनेक क्षेत्रों में उत्पादकता में वृद्धि एवं कार्पोरेट क्षेत्र की लाभप्रदता में सुधार जैसे घटक।

1.13 वर्ष 2005-06 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राजकोषीय घाटा अनुपात 4.1 प्रतिशत था जबकि बजट में अनुमान 4.3 प्रतिशत का था। सकल राजकोषीय घाटे में यह

सुधार पूंजी परिव्यय में कमी तथा विनिवेश के द्वारा हुई आय की उपलब्धता के कारण हुआ। राजस्व घाटा, यद्यपि वास्तविक रूप से कम था परंतु 2005-06 के बजट अनुमान के अनुरूप सकल घरेलू उत्पाद के 2.7 प्रतिशत के स्तर पर बना रहा।

1.14 व्यापक मुद्रा (एम₃) में 2005-06 के दौरान 17.0% वृद्धि हुई जो कि पिछले साल 12.1% थी और 2005-06 के वार्षिक नीति वक्तव्य में जो 14.5% अनुमानित थी। वाणिज्य क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष बैंक ऋण में वृद्धि 27.0% थी जोकि पिछले वर्ष के 22.8% के मुकाबले अधिक थी। 2005-06 के दौरान सरकार के निवल बैंक ऋण में 20,386 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई जो 2004-05 में 1,670 करोड़ रुपए थी तथा जो नवंबर 2005 से मार्च 2006 के दौरान चलनिधि उपलब्ध कराने का सूचक है। बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्ति बढ़ी जो रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा निवल आस्ति में वृद्धि का सूचक है। अनिवासी विदेशी मुद्रा जमाराशियों में 2005-06 के दौरान 16,876 करोड़ की कमी आई जबकि 2004-05 में 802 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई थी। यह कमी दिसंबर 2005 में प्रमुख रूप से इंडिया मिलेनियम डिफॉजिट के भुगतान (7.1 बिलियन अमरीकी डॉलर अथवा 31,959 करोड़ रुपए) के कारण हुई।

1.15 रिजर्व बैंक वर्ष के दौरान सरकारी प्रतिभूति बाजार और विदेशी मुद्रा बाजार में सुदृढ़ता और चलनिधि बढ़ाने के उपाय करता रहा। 2005-06 के दौरान वित्तीय बाजार सामान्यतया सुचारु रूप से चलता रहा यद्यपि वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान सभी समूहों में ब्याज दरों में वृद्धि जारी रही। चौथी तिमाही में इंडिया मिलेनियम डिफॉजिट भुगतान के कारण नकदी की कुछ तंगी को छोड़कर, निरंतर ऋण वृद्धि और सरकार के पास नकद की वृद्धि के बीच चलनिधि की स्थिति सामान्यतया सुगम रही। चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत बकायों से शांत होने वाली चलनिधि की कुल अधिकता बनी रही क्योंकि बाजार स्थिरीकरण योजना (एसएमएस)। केंद्र सरकार के अधिशेष नकद मिलकर मार्च से अक्टूबर 2005 तक के बीच थोड़ा सा अधिक हो गई थी परंतु उसके बाद निरंतर घटते रहे। मांग मुद्रा, बाजार रेपो और जमानती उधार लेने और ऋण देने वाले (सीबीएलओ) खंड में रात भर की दरें जो कि अक्टूबर 2005 तक चलनिधि समायोजन सुविधा दर कोरिडोर के न्यूनतम स्तर के आसपास थी, नवंबर में बढ़नी शुरू हो गई क्योंकि चलनिधि की स्थिति में अधिशेष की तरफ से घाटे की ओर रुख होने के कारण बाजार के कुछ सहभागियों के पास चलनिधि और जमानती प्रतिभूतियां दोनों की कमी होने लगी। रात भर की दरें जो चलनिधि समायोजन सुविधा रिवर्स रेपो दर के आसपास थीं, विद्यमान चलनिधि की परिस्थितियों की प्रतिक्रिया स्वरूप तेजी से बढ़ गईं। मांग मुद्रा खंड में रात भर की दरें 2005-06 की तीसरी तिमाही में, चलनिधि समायोजन निधि

कोरिडोर से ऊपर चली गई, लेकिन उसी तिमाही में जमानती बाजार की दरें चलनिधि समायोजन सुविधा दर के उच्चतर स्तर पर पहुँच गई। मांग मुद्रा बाजार में ब्याज दर अक्टूबर 2005 में औसतन 5.12% थी जो बढ़कर फरवरी 2006 में 6.93 % हो गई जो मार्च 2006 में घटकर 6.58% पर आ गई। वर्ष के दौरान उल्लेखनीय और वांछित गतिविधि थी। मुद्रा बाजार की गतिविधि का असंपाश्वर्कृत मांग मुद्रा खंड से संपाश्वर्कृत उधार लेने और उधार देने संबंधी दायित्व वाले बाजार की ओर पर्याप्त अंतरण।

1.16 61 से 90 दिनों तक की परिपक्वता वाले वाणिज्य पत्रों पर भारित औसत बट्टा दर मार्च 2005 के 5.89% से बढ़कर मार्च 2006 में 8.72% हो गई। 15 जुलाई 2006 की स्थिति के अनुसार उसी परिपक्वता वाले वाणिज्य पत्रों की भारित औसत बट्टा दर 176 अंक घटकर 6.96 प्रतिशत हो गई। सरकारी प्रतिभूति बाजार में 91 और 364 दिन के खजाना बिलों की प्राथमिक बाजार आय अप्रैल 2005 के अंत के क्रमशः 5.12 प्रतिशत और 5.60 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2006 के अंत में क्रमशः 6.11 प्रतिशत और 6.42 प्रतिशत हो गई इस अवधि में 182 दिवसीय खजाना बिल पर होने वाली आय 5.29 प्रतिशत से बढ़कर 6.61 प्रतिशत हो गई। 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन के खजाना बिलों की प्राथमिक बाजार आय अप्रैल 2006 में हुई नीलामी में क्रमशः 5.49 प्रतिशत, 6.14 प्रतिशत और 6.06 प्रतिशत थी। 5 वर्ष और 10 वर्ष की अवशिष्ट परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर आय में 2005-06 के दौरान क्रमशः 87 और 84 आधार अंकों की वृद्धि हुई।

1.17 इक्विटी बाजार में, बीच-बीच में सुधार के साथ तेजी देखी गई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में (1978-79=100) अप्रैल 2005-06 के दौरान तेजी से 73.7 की वृद्धि हुई, बिंदु-दर-बिंदु आधार पर, जो कि विदेशी संस्थागत निवेशों और घरेलू निवेशकों द्वारा, सुदृढ़ समष्टि आर्थिक परिवेश के बीच, भारी मात्रा में निवेश के कारण हुई।

1.18 2005-06 के दौरान, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी के कारण अप्रत्याशित उच्च दबाव के बावजूद, भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति सुगम रही। भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात लगातार चौथे वर्ष भी बहुत अच्छा रहा, यह औसतन 24 प्रतिशत वार्षिक रहा जिसका कारण प्रौद्योगिकी उन्मुख घरेलू निर्माण में बढ़ती प्रतियोगिता थी। उत्साहवर्धक निवेश कार्यक्रमों के साथ-साथ तेल से इतर आयातों में वृद्धि देखी गई। अगोचर खाते में और भी विस्तार के कारण अधिशेष में वृद्धि हुई जो मुख्यतः सॉफ्टवेयर तथा कारोबारी सेवाओं के निर्यात के कारण और निजी प्रेषणों के कारण था जिसके द्वारा व्यापार घाटे के लगभग 4/5 हिस्से का वित्तपोषण हो पाया। चालू खाता घाटा 2005-06 के दौरान बढ़ा

जो कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय ऊंची कीमतों और सुदृढ़ औद्योगिक कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप आयात में वृद्धि के संचित प्रभावों से प्रतिबिंबित होता है। फिर भी सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में चालू खाता घाटा फिर भी मध्यम रहा। पूंजी प्रवाह के प्रमुख घटकों विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, संविभाग निवेश और अनिवासी भारतीयों से प्राप्त जमा एक साल पहले की तुलना में अधिक जो घरेलू वित्तीय आस्तियों की भारी मांग और अर्थव्यवस्था की वृद्धि में बढ़ती रुचि से प्रतिबिंबित होता है। प्रत्यक्ष और विदेशी संविभाग निवेश - दोनों प्रवाहों में 2005-06 के दौरान वृद्धि हुई। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 2005-06 के दौरान 28.0 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई तथा यह सकारात्मक निवेश माहौल, अधिक वृद्धि की संभावनाओं और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को औचित्यपरक तथा उदारीकृत बनाने एवं प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयासों के माहौल में हुआ। संविभाग इक्विटी प्रवाह 2005-06 के दौरान और बढ़ा तथा इसका प्रमुख कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अधिक निवेश किया जाना रहा।

1.19 भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति 2006-07 के दौरान अब तक सुगम बनी हुई है। वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात में अप्रैल-सितंबर 2006 के दौरान सुदृढ़ वृद्धि हुई, हालांकि यह पिछले वर्ष के मुकाबले कम थी। तेल से इतर आयात में तीव्र कमी देखने में आई। आंशिक रूप से यह सोना और चांदी के आयात के कमी के कारण थी। निवेश की मांग के चलते पूंजी माल के आयात में वृद्धि हुई, यद्यपि उनमें भी उच्च आधार पर कुछ कमी देखने में आई। कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में और वृद्धि के मद्देनजर तेल का आयात भारी मात्रा में होता रहा। 2006-07 की पहली तिमाही के दौरान अगोचर खातों में अधिशेष की स्थिति उत्साहवर्धक बनी रही जिसका कारण सॉफ्टवेयर और अन्य व्यापारिक सेवाओं का निर्यात और निजी प्रेषण प्रमुख थे तथा जिन्होंने व्यापार घाटे के दो-तिहाई भाग को वित्तपोषित किया। 2006-07 की पहली तिमाही के दौरान चालू खाता घाटा एक वर्ष की तुलना में बढ़ा जो बढ़े हुए व्यापार घाटे से सूचित होता है।

1.20 वर्ष 2005 के दौरान भारत संविभागीय आवकों के मामले में सबसे आगे रहा। चालू खाता घाटे की अपेक्षा पूंजी आवक अत्यधिक अधिक रहा जिसके चलते, 2005-06 के दौरान भुगतान संतुलन में समग्र रूप से अधिशेष की स्थिति देखने में आई। उसके परिणामस्वरूप, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 10.1 बिलियन अमरीकी डॉलर की वृद्धि हुई और वह भंडार मार्च 2006 के अंत में 151.6 प्रतिशत बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जो कि उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं में 5वां सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय आरक्षित भंडार रहा।

अनुसूचित वाणिज्य बैंक :

1.21 वर्ष 2005-06 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र वास्तविक आर्थिक कार्यकलापों में उभार प्रदर्शित किया है। सुदृढ़ समष्टिगत आर्थिक माहौल की पृष्ठभूमि में, बैंक ऋण में लगातार दूसरे वर्ष भी सुदृढ़ विस्तार देखने में आया। ऋण की मांग भी व्यापक आधार पर देखने में आई जिसमें कि आवास और खुदरा क्षेत्र अग्रणी रहे। जमा में वृद्धि, यद्यपि पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रही फिर भी वह अधिक ऋण की मांग की पूर्ति करने में अपर्याप्त रही जिसकी वजह से बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों को बेचकर चलनिधि जुटाने के लिए मजबूत होना पड़ा। 1989 में बैंकों के राष्ट्रीकरण के बाद यह पहला अवसर है कि सरकारी प्रतिभूतियों में बैंकों का निवेश वास्तविक रूप से (19,514 करोड़ रुपए) एक वर्ष में कम हो गया। उसी प्रकार, कार्पोरेट क्षेत्र के बांडों /डिबेंचरों/शेयरों में वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों का निवेश भी कम हुआ।

1.22 सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में बैंकों की धारिता मार्च 2006 के अंत में घटकर निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 31.3 प्रतिशत हो गई जो कि मार्च 2005 के अंत में 38.2 प्रतिशत थी। यद्यपि अधिशेष सांविधिक चलनिधि अनुपात की धारिता मार्च 2006 के अंत में 1,45,257 करोड़ रुपए थी परंतु अब बैंक सांविधिक चल निधि अनुपात संविभाग में राशि की धारिता 25 प्रतिशत की न्यूनतम सांविधिक अनिवार्यता के आसपास रखते हैं।

1.23 सरकारी क्षेत्र के बैंकों की एक साल से अधिक की परिपक्वता वाली जमा राशियों पर ब्याज दर अप्रैल 2005 के 5.75-6.50 से बढ़कर मार्च 2006 में 5.75 -7.25 प्रतिशत हो गई। उसी अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की बेंचमार्क मूल उधार दरें 10.25 से 11.25 प्रतिशत और 10.0 से 14.50 प्रतिशत क्रमशः के परास (रेंज) में अपरिवर्तित रहे। उसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों की बेंचमार्क प्राथमिक मूल उधार दरें 11.00 से 13.50 प्रतिशत के परास (रेंज) से 11.00 से 14.00 के परास (रेंज) पहुंच गई। सरकारी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों के संबंध में मीयादी ऋणों के लिए मध्य उधार दरें (जिस पर अधिकतम कारोबार किया जाता है) मार्च 2006 के अंत में 8.50 से 12.00 प्रतिशत के परास (रेंज) में रहीं जबकि दिसंबर 2005 में ये दरें 8.00 से 12.00 प्रतिशत के परास (रेंज) में थीं। (अनंतिम)

1.24 एक समूह के रूप में, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल लाभ 2005-06 के दौरान बढ़े (सारणी 1.1)। ऋण वृद्धि में तेजी से वृद्धि को आस्ति की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार का भी समर्थन मिला। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल और निवल अनर्जक आस्तियाँ वास्तविक मात्रा की दृष्टि से और ऋण और अग्रिमों की मात्रा की दृष्टि से भी कम हुईं। यह प्रवृत्ति सभी समूह के बैंकों में

देखने में आई। सुदृढ़ समष्टि आर्थिक माहौल तथा रिज़र्व बैंक/सरकार द्वारा किए गए विविध संस्थागत उपायों के कारण ऋण वसूली के परिवेश में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

1.25 जोखिम भारित आस्तियों में तीव्र वृद्धि, कुछ क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण में जोखिम भार की वृद्धि तथा बाजार जोखिम के लिए पूँजी प्रभार लगाए जाने के बावजूद बैंक जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात कमोवेश पिछले वर्ष के स्तर पर बनाए रखने में सक्षम रहे। टीयर I पूँजी पर्याप्तता अनुपात मार्च 2006 में पर्याप्त बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गया जो कि मार्च 2005 में 8.4 प्रतिशत था, यह आंशिक रूप से टीयर II कैपिटल से निवेश घटबढ़ के लिए आरक्षित निधि (आइएफआर) के अंतरण के कारण और आंशिक रूप से आरक्षित निधि और अधिशेष राशि में वृद्धि तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों पूँजी बाजारों से उगाहे गए नए पूँजी संसाधनों के कारण था। उच्चतर टीयर I अनुपात का मतलब है कि टीयर II मार्ग के माध्यम से अधिक पूँजी निधि उगाहने के लिए अधिक अवसर उपलब्ध हैं।

सहकारी बैंक

1.26 वर्ष 2005-06 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों के परिचालनों में मध्यम स्तर का सुधार देखने में आया जो कि प्रमुख रूप से जमा में वृद्धि के कारण था। यद्यपि ऋण और अग्रिमों तथा निवेशों में भी मध्यम स्तर की वृद्धि देखने में आई परंतु प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और कमजोर तबके को दिए गए ऋणों तथा गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात वाले निवेशों में बहुत अधिक वृद्धि हुई। निधियों के अल्पावधिक नियोजन में भी तीव्र वृद्धि देखी गई। अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के वित्तीय कार्यनिष्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। शहरी सहकारी बैंकों की आस्ति गुणवत्ता में भी वास्तविक रूप से और ऋण संविभाग के संबंध में भी बहुत अधिक सुधार हुआ है।

1.27 समग्र ग्रामीण सहकारी बैंकों के कारोबारी परिचालन के सभी खंडों, अल्पावधि और दीर्घावधि, में 2004-05 के दौरान विस्तार हुआ। वित्तीय क्षेत्र के अन्य खंडों में वृद्धि के अनुरूप ऋण में भी तीव्र वृद्धि देखने में आई जबकि जमा में मध्यम स्तर की वृद्धि हुई। परंतु संस्थाओं के बीच बहुत व्यापक अंतर देखने में आया। अल्पावधि संरचना के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंकों ने कम लाभ कमाया, लेकिन मध्यवर्ती सहकारी बैंकों ने उच्चतर लाभ कमाए। समग्रतः प्राथमिक ऋण समितियाँ समग्र रूप से घाटे में चलती रहीं यद्यपि उनमें से कई ने लाभ भी कमाए। दीर्घावधि सहकारी संरचना के मामले में यद्यपि राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने घाटा उठाया तथापि प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों ने अपनी स्थिति में बहुत अधिक सुधार किया। वर्ष के दौरान प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के सभी तरह के ग्रामीण सहकारी बैंकों

सारणी 1.1: वित्तीय क्षेत्र के चुनिंदा संकेतक : 2005-06

श्रेणी	संकेतक	2004-05	2005-06	
1	2	3	4	
1. अनुसूचित वाणिज्य बैंक	क) प्रमुख समुच्चय/जोड़ में वृद्धि (प्रतिशत)			
	सकल जमाराशियां	16.6	17.8	
	ऋण और अग्रिम	33.2	31.8	
	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	9.4	-1.0	
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)			
	परिचालनगत लाभ	2.2	2.0	
	निवल लाभ	0.9	0.9	
	विस्तार	2.8	2.8	
	ग) अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)			
सकल अनर्जक आस्तियाँ	5.2	3.3		
निवल अनर्जक आस्तियाँ	2.0	1.2		
2. शहरी सहकारी बैंक	क) प्रमुख समुच्चय/जोड़ में वृद्धि(प्रतिशत)			
	जमाराशियां	-4.7	6.9	
	ऋण	-1.6	5.2	
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)@			
	परिचालनगत लाभ	0.8	1.1	
	निवल लाभ	0.2	0.5	
	विस्तार	1.8	1.9	
	ग) अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)			
	सकल अनर्जक आस्तियाँ	23.4	19.7	
निवल अनर्जक आस्तियाँ	12.5	9.6		
3. ग्रामीण सहकारी बैंक	क) संख्या		1,09,924 -	
	ख) प्रमुख समुच्चय / जोड़ में वृद्धि (प्रतिशत)			
	जमाराशियां	3.3	-	
	ऋण	9.0	-	
	ग) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)@			
	लाभ अर्जक सोसाइटियाँ (संख्या)	47,610	-	
	घाटे में चल रही सोसाइटियाँ (संख्या)	61,872	-	
	कुल घाटा/हानि (करोड़ रुपए)	232	-	
	घ) अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)*	24.4	-	
4. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएँ	क) प्रमुख समुच्चय/जोड़ में वृद्धि (प्रतिशत)#			
	मंजूरी	-45.1	38.9	
	संवितरण	-37.0	33.9	
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)**			
	परिचालनगत लाभ	1.2	1.4	
	निवल लाभ	0.8	1.0	
	विस्तार	1.6	1.8	
	ग) अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)**			
	निवल अनर्जक आस्तियाँ	4.0	1.1	
5. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों के सिवाय)	क) प्रमुख समुच्चय/जोड़ में वृद्धि (प्रतिशत)			
	जनता की जमाराशियाँ	-9.1	-32.1	
	ख) वित्तीय संकेतक (कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)			
	निवल लाभ	1.6	0.4	
	ग) अनर्जक आस्तियाँ (अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में)##			
	निवल अनर्जक आस्तियाँ	2.5	0.4	
	6. अवशिष्ट गैर- बैंकिंग कंपनियां (आरएनबीसी)	क) प्रमुख समुच्चय/जोड़ में वृद्धि (प्रतिशत)		
		जमाराशियां	8.3	21.5
		निवल लाभ	0.5	0.7

@ : अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित हैं।

* : प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए बकाया राशियाँ शामिल हैं।

: आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, आइडीएफसी, सिडबी, आइवीसीएफ, आइसीआइसीआइ उद्यम, टीएफसीआइ, एलआइसी और जीआइसी, से संबंधित हैं।

** : आइएफसीआइ, आइआइबीआइ, आइडीएफसी, एक्जिज बैंक, टीएफसीआइ, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी से संबंधित हैं।

: रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाली कंपनियों के लिए (कवरेज में अंतर के साथ)

की आस्तियों की गुणवत्ता में सुधार आया। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के वसूली में सुधार के कारण उनके बकायों के अनुपात में कमी आई है।

वित्तीय संस्थाएं

1.28 अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता की स्वीकृति और उनके संवितरण में 2005-06 के दौरान बहुत अधिक सुधार दर्ज किया गया। वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता की स्वीकृति और उनके संवितरण में क्रमशः 38.9% और 33.9% की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष में क्रमशः 45.1% और 37.0% की तीव्र गिरावट देखने में आई। 2005-06 के दौरान तकरीबन सभी श्रेणी की वित्तीय संस्थाओं में उच्च वृद्धि देखने में आई जबकि उसकी तुलना में 2004-05 के दौरान उनके निष्पादनों में भिन्नता पाई गई थी।

1.29 वित्तीय संस्थाओं की पूंजी पर्याप्तता का अनुपात घाटे वाली दो संस्थाओं को छोड़कर, निर्धारित मानदंडों से बहुत उपर बना रहा। परंतु आइआइबीआइ और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कापोरेशन ऑफ इंडिया के मामलों में जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात उनके निरंतर वित्तीय घाटे के कारण वर्ष के दौरान और कम हो गया।

1.30 कम लागत के साथ उच्चतर उधार दरों के कारण वित्तीय संस्थाओं को अधिक लाभ हुआ और अधिक कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल ब्याज आय 2005-06 में बढ़कर 1.8 प्रतिशत हो गई जो 2004-05 में 1.6 प्रतिशत थी। वित्तीय संस्थाओं की ब्याज से इतर आय में भी वर्ष के दौरान बहुत अधिक वृद्धि हुई। परंतु परिचालन व्यय लगभग दुगुना हो जाने के कारण वित्तीय संस्थाओं की लाभप्रदता में कमी हुई।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

1.31 गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी के सिवाय) की मूल आस्तियों/देयताओं में 2005-06 के दौरान 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई थी जबकि 2004-05 में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की निधियों के प्रमुख स्रोत उधार होते हैं जिसमें 2005-06 के दौरान 2.6 प्रतिशत की न्यूनतर से वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। स्वाधिकृत निधि (पूंजी और आरक्षित निधि) में थोड़ी सी वृद्धि दर्ज हुई परंतु 2005-06 के दौरान जनता की जमाराशियों में गिरावट दर्ज की गई। आस्ति के संबंध में, ऋण और अग्रिमों तथा किराया खरीद आस्तियों में, दोनों को मिलाकर जिनका हिस्सा कुल आस्तियों में तीन चौथाई से अधिक रहा, यद्यपि 2005-06 के दौरान ऋण और अग्रिमों में 27.8 प्रतिशत की गिरावट आई परंतु किराया खरीद में 38.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

1.32 गैर बैंकिंग कंपनियों के समूह में, किराया खरीद वित्त कंपनियों तथा उपस्कर लीजिंग कंपनियों की आस्ति/देयताओं में मार्च 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान वृद्धि हुई जबकि निवेश और ऋण कंपनियों की आस्तियां और देयताओं में गिरावट आई। मोटे तौर पर यह जमा और उधार के माध्यम से उगाहे गए संसाधनों से यह प्रतिबिंबित होती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी समूह के अंतर्गत किराया खरीद वित्त कंपनियों का समूह सबसे बड़ा था जिसका मार्च 2006 के अंत में सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की कुल आस्तियों और देयताओं में हिस्सा 80.7 प्रतिशत था, उसके बाद बहुत कम उपस्कर लीजिंग कंपनियों (9.8 प्रतिशत) और निवेश कंपनियों का (4.5 प्रतिशत) तथा ऋण कंपनियों (3.9 प्रतिशत) का हिस्सा था।

2005-06 के दौरान गतिविधियां

1.33 वर्ष 2005-06 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की तुलना में 8.9 प्रतिशत अधिक रही। तदनुसार के द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने दिसंबर 2006 में अनुमान लगाया कि 2005-06 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 8.4 प्रतिशत की दर से होगी जो कि फरवरी 2006 में जारी किए गए अग्रिम अनुमान 8.1 प्रतिशत से ऊपर है। इस वृद्धि का कारण, विनिर्माण जिसकी वृद्धि अप्रैल से अगस्त 2006 के दौरान द्विअंकीय (11.8) रही और खनन तथा विद्युत क्षेत्र थे। अप्रैल-अगस्त 2006 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि अप्रैल-अगस्त 2005 में 8.7 प्रतिशत के मुकाबले उच्चतर रही। सेवा क्षेत्र में अप्रैल-जून 2006 में द्वि-अंकीय, 10.5 प्रतिशत की (अप्रैल-जून 2005 में 10.1 प्रतिशत), 'व्यापार, होटल, रेस्ट्रॉ, परिवहन, भंडारण और संचार' (अप्रैल-जून 2006 में 13.2 प्रतिशत) के आधार पर प्रभावी वृद्धि दर्ज की। सेवा क्षेत्र के कारोबारों के प्रमुख सूचक यह संकेत देते हैं कि 2005-06 के दौरान दर्ज की गई सुदृढ़ वृद्धि 2006-07 के प्रारंभिक महीनों में बराकरार रही।

1.34 थोक मूल्य सूचकांक में उतार चढ़ाव के आधार पर मापी गई इस स्फीति, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 21 अक्टूबर 2006 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गया जबकि मार्च 2006 के अंत में यह 4.1 प्रतिशत था। चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 (14 अक्टूबर 2006 तक) के दौरान प्राथमिक वस्तुओं, विनिर्मित उत्पादों और 'ईंधन, बिजली, प्रकाश और लूब्रिकैंट' की कीमतों में क्रमशः 7.8 प्रतिशत, 4.5 प्रतिशत और 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष की अवधि के दौरान यह क्रमशः 2.8 प्रतिशत, 2.8 प्रतिशत और 10.6 प्रतिशत रही थी। प्राथमिक खाद्य वस्तुओं जोकि प्रमुखतः गेहूं, दालों, फलों और दूध की कीमतों के कारण 2006-07 में अब तक, हेडलाइन स्फीति पर वृद्धि का दबाव रहा। विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में स्फीति प्रमुखतः धातुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण रहा।

1.35 राजकोषीय वर्ष 2006-07 (13 अक्टूबर 2006 तक) के दौरान व्यापक मुद्रा (एम₃) में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष यह वृद्धि 6.1 प्रतिशत थी। वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मुद्रा आपूर्ति में (एम₃) 19.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सरकार को निवल बैंक ऋण में वित्तीय वर्ष (13 अक्टूबर 2006 तक) के दौरान, पिछले वर्ष की तदनरूपी अवधि में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 3.0 की वृद्धि हुई। वाणिज्यिक क्षेत्रों को बैंक ऋण में पिछले वर्ष की उसी अवधि की 26.4 प्रतिशत की तुलना में, 26.9 प्रतिशत वृद्धि हुई। आरक्षित मुद्रा में वर्ष 2006-07 के दौरान (20 अक्टूबर 2006 तक) चलनिधि की स्थिति में विपरीत स्थिति दिखाई दी जोकि रिजर्व बैंक के चलनिधि प्रबंध परिचालनों में प्रमुख रूप से प्रदर्शित होती है। प्रणाली में चलनिधि की अधिकता का प्रमाण चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत अधिक बकाया राशि के रूप में बाजार स्थिरीकरण योजना, रिजर्व बैंक के पास केंद्र सरकार की नकदी जमाराशि से मिलता है जोकि 20 अक्टूबर 2006 को 69, 153 करोड़ रुपए था जबकि वह मार्च 2006 के अंत में 85, 140 करोड़ रुपए था।

1.36 राजकोषीय वर्ष 2006-07 के दौरान बैंक जमा राशियों और ऋण में तीव्र वृद्धि दर्ज हुई। राजकोषीय वर्ष 2006-07 (13 अक्टूबर 2006 तक) के दौरान बैंक जमा राशि और बैंक ऋण में क्रमशः 1,85,244 करोड़ रुपए (8.8 प्रतिशत) और 1,36,643 करोड़ रुपए (9.1 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जोकि 2005-06 की उसी अवधि के दौरान क्रमशः 1,15,309 करोड़ रुपए (6.5 प्रतिशत) और 1,19,168 करोड़ रुपए (10.3 प्रतिशत) थी। सुदृढ़ समष्टि आर्थिक गतिविधियों के मद्देनजर बैंक ऋण की मांग अधिक बनी रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर ऋण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 13 अक्टूबर 2006 की स्थिति के अनुसार 30.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो एक साल पहले 31.8 प्रतिशत बढ़ा था। बैंक ऋण के क्षेत्रवार निधि नियोजन संबंधी अनंतिम सूचना से संकेत मिलता है कि खुदरा ऋणों में जून 2006 के अंत तक वर्ष-दर-वर्ष 47.0 की वृद्धि हुई तथा आवास ऋणों में वृद्धि 54.0 प्रतिशत रही। वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र को दिए गए ऋणों में 102 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जून 2006 के अंत में, उद्योग और कृषि के लिए ऋण में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि क्रमशः 27 प्रतिशत और 37 प्रतिशत रही।

1.37 भारतीय वित्तीय बाजार 2006-07 के दौरान मोटे तौर पर व्यवस्थित रहे यद्यपि सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में कुछ दबाव देखने में आए। मांग मुद्रा की दरों में 52 आधार बिंदु की कमी देखने में आई जो कि मार्च 2006 में 6.6 प्रतिशत थी तथा जो अगस्त 2006 के दौरान 6.1 प्रतिशत हो गई। सितंबर 2006 में,

मांग मुद्रा का मासिक औसत बढ़कर 6.3 प्रतिशत हो गया जोकि महीने के उत्तरार्ध में प्रमुखतः अग्रिम कर भुगतान और त्योहार के मौसम में मुद्रा की अधिक मांग के कारण अधिक ऋण की वृद्धि के फलस्वरूप अस्थायी चलनिधि के दबाव के कारण था। मासिक औसत मांग दर भी अक्टूबर 2006 के दौरान बढ़कर 6.8 प्रतिशत चलनिधि की स्थिति सुगम होने के कारण, सितंबर 2006 में 6.3 प्रतिशत हो गई। मांग मुद्रा की दरें सामान्यतः रिवर्स रेपो दर के निकट बनी रहीं। वाणिज्य पत्र बाजार की गतिविधियों में वृद्धि हुई। इससे वाणिज्य पत्रों की बकाया राशि में 90.0 प्रतिशत की वृद्धि होकर बकाया राशि सितंबर 2006 के अंत में 24,419 रुपए, हो गई जो कि मार्च 2006 के अंत में 12,718 करोड़ रुपए थी। वाणिज्य पत्र पर भारित औसत बड़ा दर, उक्त अवधि में 8.6 प्रतिशत से घटकर 7.7 प्रतिशत हो गई। जमा प्रमाणपत्र की भारित आस्त बड़ा दर 15 सितंबर 2006 को थोड़ा घटकर 8.5 प्रतिशत हो गई जो कि मार्च 2006 के अंत में 8.6 थी। जमा प्रमाणपत्रों की राशि में वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान (15 सितंबर 2006 तक) 46.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे कुल बकाया 63, 864 करोड़ रुपए हो गया।

1.38 91 दिवसीय खजाना बिल की प्राथमिक आय 26 अक्टूबर 2006 को बढ़कर 6.6 प्रतिशत हो गई जो कि मार्च 2006 के अंत में 6.1 प्रतिशत थी। दूसरी ओर 10 वर्ष वाली सरकारी प्रतिभूतियों पर आय 30 अक्टूबर 2006 को 7.6 प्रतिशत हो गई जो कि मार्च 2006 के अंत में 7.5 प्रतिशत थी। दर में वृद्धि के कई कारण थे, जैसे (i) कच्चे तेल की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मद्देनजर जिससे ब्याज दर में अनिश्चितता उत्पन्न हुई अस्थिर स्फीति की प्रत्याशाएं, (ii) सरकारी और निजी क्षेत्रों में निधियों के लिए निरंतर ऋण की प्रतियोगी मांग और अनवरत ऋण वृद्धि वैश्विक बाजार के कुछ प्रभाव; और (iii) वर्ष की दूसरी छमाही में केंद्र द्वारा अधिक उधार लिए जाने की संभावनाओं के चलते बाजार संसाधनों पर अधिक दबाव होने की आशंका।

1.39 ऋण बाजार में जमा और उधार देने की दरों में वृद्धि हुई क्योंकि ऋण की मांग अधिक थी। बैंकों ने अपनी जमा दरों में सभी विविध प्रकार की परिपक्वता के लिए मार्च 2006 और अक्टूबर 2006 के बीच 50 से 75 आधार अंकों तक वृद्धि की। बहुत से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने अपनी बेंचमार्क प्राथमिक उधार दरों में 50 से 100 आधार अंक तक उसी अवधि के दौरान वृद्धि की। विदेशी बैंकों ने उस अवधि में अपनी बेंचमार्क प्राथमिक उधार दरों में बदलाव न करके उसे 10.00 से 14.50 प्रतिशत बनाए रखा।

1.40 भारतीय विदेशी मुद्रा बैंक सामान्यतः चालू वित्तीय वर्ष में अब तक (27 अक्टूबर 2006 तक) व्यवस्थित रहा। रुपए की विनिमय दर में जो कि मार्च 2006 के अंत में 44.61 रुपए प्रति अमरीकी

डॉलर थी, 27 अक्टूबर 2006 के अंत में 1.4 प्रतिशत के हास के कारण कमी आई और यह 45.22 हो गई। रुपए ने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में (जैसे, यूरो, पौंड स्टर्लिंग और जापानी येन) हास की प्रवृत्ति दर्शाई। चालू वित्त वर्ष के दौरान (27 अक्टूबर 2006 को) रुपए में यूरो की तुलना में 5.5 प्रतिशत, पौंड स्टर्लिंग की तुलना में 9.0 प्रतिशत और जापानी येन की तुलना में 0.5 प्रतिशत मूल्य हास हुआ। अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपए में आया उतार-चढ़ाव इन मुद्राओं के संबंध में प्रमुख रूप से अमरीकी डॉलर के मूल्य में हुए परिवर्तनों के कारण था। 2006-07 की पहली तिमाही के दौरान फॉरवर्ड प्रीमिया में घरेलू मुद्रा बाजार में ब्याज दर में कमी आने के साथ-साथ अमरीका में मौद्रिक नीति में कठोरता के बाद गिरावट आई तथापि 2006-07 की दूसरी तिमाही में वायदा प्रीमिया में मध्यम स्तर की वृद्धि हुई।

1.41 वर्ष 2006-07 (31 अक्टूबर 2006 तक) के दौरान इक्विटी बाजार में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव नज़र आया। मई-जून 2006 के दौरान स्टॉक बाजार में तीव्र सुधार देखने में आया जो कि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों के तालमेल में था। उसके बाद बाजार में कुछ घाटे की पूर्ति हुई क्योंकि मुंबई स्टॉक एक्स्चेंज 3 नवंबर 2006 को बढ़कर 13,131 अंक पर पहुंच गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय इक्विटी बाजार में किए गए निवेशों, कंपनी जगत के अच्छे परिणामों के फलस्वरूप और प्रमुख एशियाई इक्विटी

बाजारों में मजबूती के रुख के कारण बाजार में सकारात्मक रुख दिखा। इसके पीछे एफओएमसी बैठक में अमरीकी फेडरल ब्याज दरों में परिवर्तन न करने के लिए किया गया निर्णय, कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में गिरावट था।

1.42 भारत का व्यापारिक निर्यात अप्रैल-सितंबर 2006 के दौरान 22.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की जबकि पिछले साल की उसी अवधि में 34.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रैल-सितंबर 2006 के दौरान आयात में समग्र रूप से वृद्धि मुख्यतः तेल से इतर आयात में वृद्धि मध्यम (11.5 प्रतिशत एक वर्ष के पीछे की वृद्धि 47.9 प्रतिशत के मुकाबले) रहने के कारण रही। व्यापार घाटा अप्रैल-सितंबर 2006 में बढ़कर 24.6 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया जो कि अप्रैल-सितंबर 2005 में 22.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था। वर्ष 2005-06 के दौरान भारत में पूंजी अंतर्वाह में जो बहुत उत्साह देखने में आया वह चालू वित्तीय वर्ष में भी जारी रहा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अनिवासी भारतीय जमा राशियों और एडीआर/जीडीआर के अंतर्गत निर्गम अप्रैल-अगस्त 2006 में, 2005 की उसी अवधि के मुकाबले अधिक थे। दूसरी ओर विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2006-07 के दौरान (13 अक्टूबर 2006 तक) 29 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवल बहिर्वाह किए। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 27 अक्टूबर 2006 को बढ़कर 167.1 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।